भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

05.04.2023 के

अतारांकित प्रश्न सं. 5435 का उत्तर

अंबलप्पुझा-एर्णाकुलम रेल लाइन का दोहरीकरण

5435. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिंक बुक में शामिल केरल की अंबलप्पुझा-एर्णाकुलम रेल लाइन के दोहरीकरण के कार्य में तेजा लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा किया है;

(ख) उपर्युक्त दोहरीकरण कार्य के लिए निविदा कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने अंबलप्पुझा-एर्णाकुलम खंड पर रेलगाड़ियों को 60 किमी प्रति घंटे की गति से चलाने के लिए दूसरी लाइन बिछाने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का केरल के एर्णाकुलम-शोरनूर खंड में तीसरी रेल लाइन बिछाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी प्राविधि क्या है;

(ङ) वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक केरल में विभिन्न रेल लाइनों के दोहरीकरण के लिए स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

अंबलप्पुझा-एर्णाकुलम रेल लाइन का दोहरीकरण के संबंध में दिनांक 05.04.2023 को लोक सभा में एडवोकेट ए.एम. आरिफ़ द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 5435 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): एणार्कुलम से अंबलप्पुझा के दोहरीकरण कार्य को तीन भागों अर्थात एणार्कुलम-कुम्बलम (7.7 किमी), कुम्बलम-तुरावुर (15.59 किमी) और तुरावुर-अंबलप्पुझा (45.86 किमी) में विभाजित किया गया है। तीनों परियोजनाओं को क्रमश: 2010-11, 2011-12 और 2015-16 के बजट में शामिल किया गया था। परियोजनाओं की वर्तमान प्रत्याशित लागत क्रमशः 595 करोड़ रुपये, 803 करोड़ रुपये और 1262 करोड़ रुपये आंकी गई है। शुरूआत में, केरल सरकार से निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने और परियोजनाओं की लागत को साझा करने का अनुरोध किया गया था। बहरहाल, केरल सरकार इसके लिए सहमत नहीं हुई है। परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए, रेलवे के 100% वित्तपोषण के साथ कार्य शुरू करने का निर्णय लिया गया है। एणार्कुलम-कुम्बलम (7.71 किमी) और कुम्बलम-तुरावुर (15.59 किमी) दोहरीकरण परियोजनाओं का विस्तृत आकलन स्वीकृत कर दिया गया है और तुरावुर-अंबलप्पुझा (45.86 किमी) के दोहरीकरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर दी गई है।

एणार्कुलम-कुम्बलम (7.71 किमी) और कुम्बलम-तुरावुर (15.59 किमी) दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए केरल में क्रमशः 4.20 हेक्टेयर और 10.30 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है। भूमि अधिग्रहण और राज्य सरकार द्वारा रेलवे को भूमि सौंपे जाने के संबंध में हुई प्रगति के आधार पर परियोजनाओं के लिए निविदा देने की प्रक्रिया शुरू की जाती है।

सभी दोहरीकरण परियोजनाएं शहरों से गुजरने वाले मौजूदा संरेखण के लगभग समतुल्य हैं और गति रेलपथ के मोड़ पर निर्भर करती है जो भूमि की उपलब्धता से प्रभावित होती है।

(घ): एणार्कुलम-षोरणूर तीसरी लाइन (107 किमी) दोहरीकरण परियोजना को 2018-19 में बजट में शामिल किया गया है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण (एफएलएस) स्वीकृत कर दिया गया है। यातायात की आवश्यकता सहित इस परियोजना से संबंधित सर्वेक्षण पूरा हो जाने और इसके परिणामों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इस परियोजना पर आगे निर्णय लेना संभव होगा।

(ङ): रेल परियोजनाएं क्षेत्रीय रेल-वार स्वीकृत और शुरू की जाती हैं न कि राज्य-वार क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। केरल में रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के दक्षिण रेल जोन के अंतर्गत आती हैं।

लागत, व्यय और परिव्यय सहित रेल परियोजनाओं का जोन-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात् www.Indianrailways.gov.in>Ministry of Railways >Railway Board >About Indian Railways >Railway Board Directorates >Finance (Budget)>Rail Budgat/Pink book (year)>Railway-wise Works Machinery & Rolling Stock Programme पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

वर्ष 2014 से, अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के बजट आवंटन और तदनुरूपी कमीशिनिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। केरल राज्य में पूर्णत:/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों पर औसत वार्षिक बजट आबंटन, 2009-14 के दौरान 372 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2014-19 के दौरान 950 करोड़ रुपए प्रति वर्ष किया गया है (जो 2009-14 के औसत वार्षिक आवंटन की तुलना में 155% अधिक है)। इन परियोजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 में वार्षिक बजट आवंटन 667 करोड़ रुपये (2009-14 के दौरान औसत वर्षित बजट आबंटन से 79% अधिक), वित्त वर्ष 2020-21 में 688 करोड़ रुपये तक (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आबंटन से 85% अधिक), वित्त वर्ष 2021-22 हेतु 1,866 करोड़ रुपये (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आबंटन से 402% अधिक) और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1,085 करोड़ रुपये (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आबंटन से 192% अधिक) तक बढ़ा दिया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 हेतु इन कार्यों के लिए अभी तक का सर्वाधिक बजट परिव्यय अर्थात 2,033 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है, जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट परिव्यय से 446% अधिक है।

*****